राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 992/2024

शांति लाल डामोर पुत्र श्री धन जी, उम्र लगभग 42 वर्ष, जाति भील निवासी हिम्मत सिंह का गढ़ा, पोस्ट रुजिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव के माध्यम से संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान)।

2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर (राज.)

3. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, संभागीय संस्कृत शिक्षा कार्यालय, संभाग उदयपुर, जिला उदयपुर (राज.)

4. प्रधानाचार्य, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, दलोट जिला प्रतापगढ़, (राज.) ----प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:- सुश्री अरुणा नेगी

प्रतिवादी(ओं) के लिए:---

माननीय जस्टिस श्री अरुण मोंगा

आदेश

07/02/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 18.12.2023 (अनुलग्नक-9) के एक आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके अनुसार नियम 1996 के नियम 2 (बी) (ii) के तहत अनुकंपा नियुक्ति से याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर इनकार कर दिया गया है कि चूंकि स्वर्गीय श्री

मांगी लाल 11.02.2023 को सेवाओं में शामिल हुए थे और 19.04.2023 पर उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं की।

2. संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः-

2.1 याचिकाकर्ता बी. ए., बी. एड. और स्वर्गीय श्री मांगी लाल के भाई हैं।

2. 2 याचिकाकर्ता के भाई को संस्कृत शिक्षा विभाग में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रतापगढ़ में प्रथम श्रेणी (संस्कृत) के शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। 19.04.2023 को उनका निधन हो गया।

2. 3 श्री मांगी लाल की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता उनके भाई होने के नाते, राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया। संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी ने निदेशक, संस्कृत शिक्षा को एक पत्र लिखा और याचिकाकर्ता को नियुक्ति की सिफारिश की।

2. 4 तथापि, निदेशक ने दिनांक 18.12.2023 के पत्र/आदेश के माध्यम से इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार किया कि चूंकि स्वर्गीय श्री मांगी लाल 11.02.2023 को सेवा में शामिल हुए थे और 19.04.2023 को उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं की। इसलिए वर्तमान रिट याचिका लगाई गई है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और आक्षेपित आदेश का भी अध्ययन किया है।

4. पारित किए जा रहे आदेश की प्रकृति को देखते हुए, उत्तरदाताओं के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा और इसलिए, नोटिस जारी करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया

है क्योंकि उनके द्वारा कोई विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

5. यहाँ आक्षेपित आदेश का एक सुक्ष्म अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उपरोक्त आदेश पारित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के दिमाग पर जो बात भारी पड़ी है, वह राजस्थान मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2 के अनुसार एक मृत सरकारी कर्मचारी की एक असंशोधित परिभाषा थी। मृत कर्मचारी की असंशोधित परिभाषा नीचे दी गई हैः -"(ख) "मृत सरकारी कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य संवर्ग की अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य सहित राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित था और जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि में देय था और जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी और जोः- (i) स्थायी, या (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद अस्थायी रूप से पद धारण करने वाला, या (iii) तत्काल/अस्थायी नियुक्ति पर नियमित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया था और जिसने एक वर्ष की निरंतर सेवा की थी।"

6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मृत कर्मचारी की असंशोधित परिभाषा में यह परिकल्पना की गई थी कि जब तक मृत कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में एक वर्ष की निरंतर सेवा के लिए परिवीक्षा में नहीं होता, तब तक वह एक मृत सरकारी कर्मचारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए आक्षेपित आदेश में यही कारण दिया गया है।

7. ऐसा लगता है कि सक्षम प्राधिकारी की दृष्टि खो गई है, यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि परिवीक्षाधीन के रूप में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा की उपरोक्त आवश्यकता को एक संशोधन करके अधिसूचना दिनांक 25.04.2012 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसके बजाय उपखंड (ख) (i) को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गयाः "(ख)" मृत

सरकारी कर्मचारी "का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य के मामलों के संबंध में कार्यरत था, जिसमें राजस्थान राज्य संवर्ग की अखिल भारतीय सेवाओं का एक सदस्य भी शामिल था और जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि में देय था और जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी और जो था, (i) स्थायी, या (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद अस्थायी रूप से एक पद पर था, जिसमें परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में परिवीक्षा की अवधि भी शामिल थी।"

8. उपरोक्त का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परिवीक्षाधीन के रूप में एक वर्ष की न्यूनतम आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात्, एक कर्मचारी, एक बार नियमित पद पर नियुक्त होने के बाद, भले ही परिवीक्षा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, वह किसी भी अन्य नियमित कर्मचारी के समान ही खड़ा होगा।

9. आधार में, आक्षेपित आदेश पारित करने वाले सक्षम प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से मृत कर्मचारी की एक अपरिवर्तित परिभाषा पर भरोसा करके कानून में भौतिक अनियमितता को अंजाम दिया।

10. आक्षेपित आदेश तदनुसार टिकाऊ नहीं है और इसे अलग रखा गया है। याचिकाकर्ता को नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेने के लिए एक नए आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है, जिससे कानून के अनुसार जल्द से जल्द निपटा जाएगा।

11. उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ तदनुसार निपटान किया गया।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।